गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 183
दि. 04.11.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

उत्तर से दक्षिण तक सड़कों पर मौत का कहर – एक ही दिन में 32 से अधिक लोगों की गई जान, तेलंगाना और राजस्थान बने देश के सबसे बड़े शोक स्थल

(जीएनएस)। मुंबई/जयपुर/हैदराबाद। देश की सड़कों पर सोमवार का दिन भय और मातम का प्रतीक बन गया। सुबह से शाम तक देश के दो सिरों—उत्तर के राजस्थान और दक्षिण के तेलंगाना—से जो दृश्य सामने आए, उन्होंने हर संवेदनशील दिल को झकझोर दिया। पलक झपकते ही जिंदगियां मिट गईं, परिवार उजड़ गए, और सड़कें खून से लाल हो गईं। एक ओर तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में आरटीसी बस और डंपर की भीषण टक्कर में 19 लोगों की मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर राजस्थान की राजधानी जयपुर में बेकाबू डंपर ने 13 लोगों को रौंद डाला। इन दोनों घटनाओं ने फिर साबित कर दिया कि भारत में सड़क सुरक्षा सिर्फ कागजों में है, जमीन पर नहीं।

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सुबह का वक्त था। लोग अपने काम पर निकल चुके थे, बसें और गाड़ियां अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थीं। हैदराबाद-बीजापुर हाईवे पर चल रही एक आरटीसी बस के यात्रियों के लिए यह दिन शायद एक सामान्य दिन होना था, लेकिन चेवेला के मिर्जागुड़ा गांव के पास मौत उनका इंतजार कर रही थी। सामने से आ रहा गिट्टी से भरा डंपर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया और बस पर गिर पड़ा। देखते ही देखते पूरा मंजर चीखों में बदल गया। 19 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 20 से अधिक घायल अस्पताल पहुंचाए गए। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और दोनों वाहन चालक शामिल थे।

मृतकों में 10 महीने का एक बच्चा और तीन बहनें—तनुशा, साई प्रिया और नंदिनी—भी थीं, जो हैदराबाद के एक कॉलेज में पढ़ती थीं। उनके पिता येल्लैया गौड़ की आंखों के सामने

उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। हाल ही में उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी, लेकिन खुशियों का वह घर कुछ ही दिनों में मातम के अंधेरे में डूब गया। एक अन्य यात्री एन. हनुमंथु का 10 वर्षीय बेटा अब अपने पिता की याद में बेसुध होकर रो रहा है। वह ट्रेन छूटने के कारण बस में सवार हुए थे—शायद नियति उन्हें वहां खींच लाई थी।

चेवेला पुलिस के अनुसार, डंपर गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहा था और उसने सीधे बस को टक्कर मार दी। गिट्टी से भरे डंपर की लदान बस के अंदर जा गिरी, जिससे यात्री बुरी तरह दब गए। बचाव दल को शव निकालने के लिए बस को काटना पड़ा। कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग गिट्टी के नीचे से मदद के लिए पुकारते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

दक्षिण के इस दर्दनाक हादसे की खबर अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उत्तर भारत के राजस्थान से भी मौत की सिहरन पैदा करने वाली घटना सामने आ गई। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में दोपहर के समय सड़कों पर अफरा-तफरी मच गई जब तेज रफ्तार डंपर ने 300 मीटर तक मौत का तांडव मचा दिया। डंपर के ब्रेक फेल हो गए और उसने कारों, बाइकों, ऑटो रिक्शाओं समेत 50 से अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में सड़क पर मलबा और शवों का ढेर लग गया। जिसने यह दृश्य देखा, उसकी रूह कांप गई।

13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 से अधिक घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बिना देर किए बचाव कार्य शुरू किया, गाड़ियों में फंसे घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया। कांवटिया अस्पताल और एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में सभी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को आपातकालीन ड्यूटी पर बुला लिया गया। हरमाड़ा थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक डायवर्ट किया, शवों को मॉर्च्युरी भेजा और डंपर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि जयपुर हादसे में हुई मौतों से वह अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की।

राजस्थान में यह 80 दिनों के भीतर छठा बड़ा सड़क हादसा है। अब तक इन हादसों में 67 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति का कारण खराब सड़क प्रबंधन, वाहन निरीक्षण की लापरवाही और चालकों की थकान या लापरवाही है।

तेलंगाना से लेकर राजस्थान तक एक ही दिन में हुई इन भयावह घटनाओं ने एक बार फिर देश की सड़क सुरक्षा नीति की पोल खोल दी है। हजारों करोड़ रुपये के बजट के बावजूद सड़कों पर सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम नदारद हैं। हर दिन औसतन 400 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकारें राहत राशि और बयान जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती हैं, लेकिन जिन घरों के चिराग इन हादसों में बुझ जाते हैं, वहां जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती।

यह दिन देश के लिए चेतावनी है—सड़कें अब सिर्फ रास्ते नहीं रहीं, वे मौत के मैदान बनती जा रही हैं। जब तक सख्त कानून, जिम्मेदार ड्राइविंग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक हर सुबह किसी न किसी परिवार के लिए अंधेरी खबर लेकर आएगी।

गाजा से एक और त्रासदी की वापसी: हमास ने तीन बंधकों के शव रेडक्रॉस को सौंपे, एक की पहचान इजरायली सैनिक ओमर न्यूत्रा के रूप में हुई

(जीएनएस)। गाजा पट्टी। युद्ध और शांति के बीच झूलती गाजा की रातों में रविवार को एक और मानवीय अध्याय जुड़ गया, जब हमास ने तीन बंधकों के शव अंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस को सौंपे। यह सौंपा जाना मात्र एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस गहराते मानवीय संकट की तस्वीर है जो गाजा और इजराइल के बीच लंबे समय से चली आ रही हिंसा के बीच हजारों परिवारों को तोड़ चुकी है। तीनों शवों को दक्षिणी गाजा की एक सुरंग से निकालकर रेडक्रॉस के हवाले किया गया, जिन्हें बाद में इजराइल लाया गया ताकि उनकी पहचान की जा सके। इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की कि उनमें से एक शव अमेरिकी-इजरायली सैनिक ओमर न्यूत्रा का है, जिसकी पहचान उसके परिवार ने की।

हमास ने अपने बयान में कहा कि ये शव भूमिगत सुरंग से प्राप्त किए गए, जो गाजा में उसके नेटवर्क का हिस्सा थी। शवों को तीन अलग-अलग ताबूतों में रखा गया था और उन्हें गाजा के दक्षिणी हिस्से से रेडक्रॉस प्रतिनिधियों के माध्यम से इजराइल को सौंपा गया। अंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस ने शवों को तेल अवीव के अबू कबीर फॉरेंसिक संस्थान भेजा, जहां विशेषज्ञ उनकी अंतिम पहचान और चिकित्सा परीक्षण कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, शवों के साथ हमास ने एक फोटो भी जारी की थी, जिसमें एक शव बैग पर मृतक

का नाम लिखा हुआ था — यह संकेत था कि शवों की पहचान पहले से ज्ञात थी।

इजराइल की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मृतक सैनिक ओमर न्यूत्रा न्यूयॉर्क में जन्मा था और उसने दोहरी नागरिकता के तहत इजरायली सेना में सेवा दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमर न्यूत्रा के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि "उसने अपने लोगों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, और अब उसकी वापसी उस प्रतीक्षा का अंत है जो दर्द से भरी थी।" हालांकि, इजराइली सैन्य सूत्रों ने यह भी कहा है कि अभी भी आठ अन्य बंधकों के शवों का कोई सुराग नहीं मिला है। माना जा रहा है कि उनमें से कई की मृत्यु गाजा में बमबारी या सुरंग ढहने जैसी घटनाओं में हुई होगी।

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहन प्रयास जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से किए गए अस्थायी युद्धविराम समझौते के तहत हमास को सभी जीवित बंधकों को 72 घंटों में सौंपना था और मृत बंधकों की जानकारी साझा करनी थी। इजराइल का आरोप है कि हमास ने जानबूझकर इस समझौते का उल्लंघन किया और कई शव अब तक छिपा रखे हैं। इजराइल ने गुरुवार को भी दो अन्य बंधकों — 84 वर्षीय अमीरम कूपर और 25 वर्षीय सहर बारूक — के शव प्राप्त किए थे, जिन्हें पहचान की पुष्टि के बाद इजराइल में पूरे सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया। उस सौंपे जाने के दौरान भी रेडक्रॉस की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी, जिसने लगातार दोनों पक्षों के बीच मानवीय संवाद को बनाए रखा है। गाजा के स्थानीय सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हमास अपने कब्जे में रखे शवों और बंदियों के प्रबंधन को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव में है। वहीं इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां यह मानती हैं कि यह आंशिक रिहाई युद्धविराम वार्ता को आगे बढ़ाने की रणनीति हो सकती है।

हिंद महासागर में सहयोग का नया अध्याय : भारतीय नौसेना का जहाज 'सावित्री' मॉरीशस पहुंचा, समुद्री साझेदारी हुई और मजबूत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत और मॉरीशस के बीच समुद्री सहयोग और सामरिक संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करते हुए भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) 'आईएनएस सावित्री' सोमवार को मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंचा। जहाज के आगमन पर मॉरीशस राष्ट्रीय तटरक्षक बल (एनसीजी) के अधिकारियों ने पारंपरिक स्वागत किया, जिसमें स्थानीय बैंड की धुनों और औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से भारतीय दल का अभिनंदन किया गया। यह दौरा न केवल दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, निगरानी और आपसी सहयोग को नए स्तर तक ले जाने का प्रतीक भी है।

'सावित्री' के आगमन से भारत और मॉरीशस के बीच रक्षा साझेदारी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हिंद महासागर के छोटे द्वीपीय देशों के साथ अपनी रणनीतिक पहुँच को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें नौसैनिक अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुद्री निगरानी और मानवीय सहायता प्रमुख हैं। रॉरीशस, जो भारत के समुद्री पड़ोसियों में से एक है, लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का विश्वसनीय भागीदार रहा है। दोनों देशों के बीच साझा समुद्री सीमाएं, सांस्कृतिक जुड़ाव और आर्थिक हित इस रिश्ते को और गहरा बनाते हैं। पोर्ट लुइस में 'सावित्री' का दल कई पेशेवर गतिविधियों में भाग लेगा। इसमें संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, आपदा प्रतिक्रिया ड्रिल, समुद्री निगरानी मिशन और तकनीकी अनुभव साझा करने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इस प्रवास के दौरान एनसीजी कर्मियों को भारतीय नौसेना की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के तहत संयुक्त अभियान संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे दोनों सेनाओं के बीच समन्वय और इंटरऑपरेबिलिटी में उल्लेखनीय सुधार होगा। भारतीय युद्धपोत 'सावित्री' का दल मॉरीशस राष्ट्रीय तटरक्षक बल के जहाजों और विमानों के साथ मिलकर अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की निगरानी करेगा। इस अभियान का उद्देश्य मॉरीशस के समुद्री इलाकों को अवैध मछली पकड़ने, समुद्री डकैती, और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से सुरक्षित रखना है।

कुलगाम में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई: जंगलों में छिपे दो आतंकी ठिकाने ध्वस्त, गैस सिलेंडर और कपड़े बरामद

(जीएनएस)। कुलगाम। दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जारी सुरक्षाबलों की मुहिम ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। कुलगाम जिले के दमहाल हंजीपोरा के घने वन क्षेत्र में सोमवार को सुरक्षाबलों ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाकर आतंकियों के दो पुराने ठिकानों का भंडाफोड़ किया और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने विशेष खुफिया सूचना के आधार पर की।

अधिकारियों ने बताया कि अभियान सुबह तड़के शुरू किया गया था। विश्वसनीय खुफिया इनपुट्स के अनुसार, अहमदाबाद और नेंगरीपोरा के बीच के घने जंगलों में आतंकियों के कुछ ठिकाने छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरकर सघन तलाशी अभियान चलाया। कई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद जवानों को झाड़ियों और पत्थरों के बीच लकड़ी और टीन से बने दो अस्थायी शरणस्थल मिले, जिनमें आतंकियों ने लंबे समय तक ठहराव किया था।

सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, इन ठिकानों से कई महत्वपूर्ण सामान बरामद हुए हैं, जिनमें गैस सिलेंडर, कपड़े, सूखे राशन का सामान, स्लीपिंग बैग, बैटरी, कंबल और कुछ दस्तावेज शामिल हैं। बरामद सामान

से यह स्पष्ट होता है कि यह ठिकाने लंबे समय तक सक्रिय रहे और इन्हें आतंकियों ने ठंडे इलाकों में सर्दियों के दौरान शरणस्थल के रूप में इस्तेमाल किया था। सभी बरामद वस्तुओं को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन ठिकानों के जरिए आतंकवादी संगठन दक्षिण कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अपनी सक्रियता बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। इन क्षेत्रों का उपयोग आतंकवादी अपने मूवमेंट के लिए "सेफ कॉरिडोर" के रूप में करते थे, जिससे उन्हें सीमावर्ती जिलों तक पहुंचने में मदद मिलती थी। इस अभियान के बाद इन रास्तों पर निगरानी और सघन कर दी गई है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है, क्योंकि इससे घाटी में आतंकियों के पुराने नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और खुफिया साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है।

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, फिलहाल इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है और आसपास के गांवों में तलाशी जारी है, ताकि किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि घाटी में पिछले कुछ हफ्तों से आतंकियों की आवाजाही के संकेत मिले थे, जिसके बाद यह अभियान चलाया गया। इस बीच, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा है कि यह तलाशी अभियान आतंकवाद के खिलाफ जारी ऑपरेशन "ऑल आउट" का हिस्सा है। पिछले एक महीने में सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में छिपे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कुलगाम, पुलवामा और शोपियां जैसे जिलों में इस तरह के अभियानों से आतंकियों की रसद और छिपने के ठिकानों की कमी होगी, जिससे उनके नेटवर्क को कमजोर करने में काफी मदद मिलेगी। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।

अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती : मजार-ए-शरीफ के पास 6 .3 तीव्रता का भूकंप

(जीएनएस)। काबुल। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में सोमवार तड़के धरती एक बार फिर डोली, और उसके साथ ही भय और विनाश का सिलसिला लौट आया। रिक्टर पैमाने पर 6.3 तीव्रता वाले भूकंप ने मजार-ए-शरीफ और उसके आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत और 260 से अधिक घायल होने की पुष्टि हुई है। प्रशासन का कहना है कि मलबे में कई लोग अब भी फंसे हुए हैं, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, यह भूकंप मजार-ए-शरीफ से लगभग 28 किलोमीटर गहराई में आया। झटके इतने तीव्र थे कि शहर की सड़कों पर भगदड़ मच गई। स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 6 बजे आए इस भूकंप का केंद्र एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में था, जहां पांच लाख से अधिक लोग रहते हैं। कई आवासीय इमारतें और पुरानी संरचनाएं पूरी तरह धराशायी हो गईं। शहर की गलियों में धूल और मलबे के बादल छा गए और लोग भयभीत होकर खुले मैदानों की ओर भागे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भूकंप का कंपन लगभग 25 से 30 सेकंड तक महसूस हुआ। इस दौरान कई घरों की दीवारें गिर गईं और दुकानों के शटर झटके से बंद हो गए। मोबाइल नेटवर्क और बिजली व्यवस्था भी कुछ समय के लिए ठप हो गई। अस्पतालों में अचानक घायल लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। समंगान प्रांत के स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता समीम जॉयंदा ने बताया कि केवल समंगान में ही सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। "कई घायल अब भी गंभीर स्थिति में हैं। राहत और बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं," उन्होंने कहा। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपनी विशेष 'पेजर प्रणाली' के माध्यम से इस भूकंप के लिए नारंगी स्तर का अलर्ट जारी किया है। इसका अर्थ है कि क्षेत्र में व्यापक जनहानि और आर्थिक क्षति की संभावना अधिक है। एजेंसी के अनुसार, यह झटका एक प्रमुख टेक्टॉनिक फॉल्ट ज़ोन से जुड़ा है, जो हाल के वर्षों में सक्रिय रहा है।

तालिबान प्रशासन के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि बल्ख और समंगान प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा,

"हमारी सैन्य और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। मलबा हटाने, घायलों को सुरक्षित निकालने और विस्थापित परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए चौबीसों घंटे काम किया जा रहा है।"

कई राहत एजेंसियों ने भी सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी और अंतरराष्ट्रीय बचाव संगठनों के स्वयंसेवक प्रभावित गांवों में अस्थायी शिविर और चिकित्सा केंद्र स्थापित कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई इलाकों में सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण बचाव दलों को पहुंचने में कठिनाई हो रही है।

अफगानिस्तान पिछले दो सालों से लगातार भूकंपीय गतिविधियों की चपेट में है। खासकर देश के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में भूकंपों की आवृत्ति बढ़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार, हेरात और बल्ख के बीच की भौगोलिक रेखा एक सक्रिय फॉल्ट ज़ोन है, जहां जमीन के नीचे टेक्टॉनिक प्लेटों की हलचल लगातार बनी रहती है। पिछले वर्ष हेरात में आए भूकंप में 1,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

तालिबान सरकार ने सभी प्रभावित जिलों में आपात राहत फंड जारी करने की घोषणा की है और घायलों को मुफ्त चिकित्सा सेवा देने का आदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएएमए) ने भी अपने बयान में अफगान नागरिकों की सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल सहयोग की अपील की है।

मेक्सिको के मिचोआकान में 'डे ऑफ द डेड' उत्सव के दौरान गोलियों की गूंज, भीड़ के बीच मेयर की हत्या

मे **(जीएनएस)**। क्सिको सिटी। परंपरागत रूप से रंगों, पुष्पों और संगीत से सजे 'डे ऑफ द डेड' (मृतकों का दिवस) उत्सव की शाम उस वक्त खून से लाल हो गई जब पश्चिमी

मेक्सिको के मिचोआकान राज्य में उरुआपान नगर पालिका के मेयर कार्लोस अल्बर्टो मैनजो रोड्रिगेज की सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात न केवल मेक्सिको बल्कि पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र को झकझोर देने वाली रही।

सात गोलियों ने छीन ली जान

राज्य के अभियोजक कार्लोस टोरेस पिना के अनुसार यह घटना शनिवार रात उस समय घटी जब मेयर शहर के ऐतिहासिक केंद्र में आयोजित उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। अचानक एक व्यक्ति भीड़ में से निकला और करीब से उन पर सात गोलियां दाग दीं। गोलियों की आवाज से अफरातफरी मच गई, लोग इधर-उधर भागने लगे और पूरा कार्यक्रम मातम में बदल गया।

गंभीर रूप से घायल मेयर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ ही मिनटों में उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दौरान नगर परिषद का एक सदस्य और एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया

हमले के तुरंत बाद तैनात सुरक्षाबलों ने स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की और जवाबी गोलीबारी की। हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हमलावर ने खुद को भीड़ में घुला दिया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उत्सव में शामिल व्यक्ति है। पुलिस को घटनास्थल से एक पिस्तौल, कई कारतूस और निगरानी कैमरों की फुटेज मिली है, जो जांच में अहम भूमिका निभा सकती है।

'कायराना हमला', पूरे देश में गुस्सा

संघीय सुरक्षा सचिव ओमार गार्सिया हार्फुच ने घटना की पुष्टि करते हुए इसे "कायरतापूर्ण और अमानवीय हमला" बताया। उन्होंने कहा, "यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक सुरक्षा पर सीधा आघात है।"

राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज़ ओब्रादोर ने भी मेयर के परिवार और नागरिकों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि "सरकार इस हत्याकांड के पीछे की हर कड़ी तक पहुंचेगी और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।"

हिंसा और कार्टेल संघर्ष का केंद्र है मिचोआकान

मिचोआकान राज्य लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी, उगाही और गिरोहबाज़ी के कारण हिंसा का पर्याय बन चुका है। यह वही इलाका है जहां "लॉस वायगेरोस" और "कार्टेल जालिस्को न्यू जेनरेशन" जैसे संगठनों के बीच लगातार खूनी संघर्ष चलता रहता है। पिछले दशक में यहां सैकड़ों राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले हो चुके हैं। उरुआपान, जहां यह हमला हुआ, को मेक्सिको का "हॉट ज़ोन" माना जाता है, क्योंकि यहां आपराधिक गिरोहों का प्रभाव सबसे अधिक है।

संपादकीय

प्रेस की आज़ादी में बाधा

इसे दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस 2 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों के खिलाफ दुराग्रह व हिंसा से मुक्ति के लिये मनाया जाता है, उसी दिन पंजाब भर में पुलिस द्वारा अखबारों को पाठकों तक पहुंचने से रोका गया। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाये जाने का उद्देश्य अभिव्यक्ति की आजादी और सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच पर मंडराते खतरों के खिलाफ चेतना जगाना रहा है। वहीं इस दिन पंजाब पुलिस ने रविवार तड़के समाचार पत्र ले जाने वाले वाहनों को रोककर कथित जांच का उपक्रम किया। फलतः लाखों पाठक आपने पसंदीदा समाचार पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते रह गए। निश्चित रूप से उन लोगों के लिये यह कष्टदायक ही रहा होगा, जिनके दिन की शुरुआत ही अखबार के साथ चाय-कॉफी से होती है। वे घंटों प्रतीक्षा करते रह गए, लेकिन पुलिस कार्रवाई के चलते उन तक समाचार पत्र नहीं पहुंचे। हालांकि, इस कार्रवाई के बाबत पुलिसिया दलील किसी के गले नहीं उतरी। पुलिस का दावा था कि यह जांच खुफिया एजेंसियों की सूचना पर आधारित थी कि इन वाहनों का उपयोग नशे, हथियार व प्रतिबंधित चीजों की तस्करी के लिये किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी प्रतिबंधित व आपराधिक श्रेणी में आने वाली किसी वस्तु का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन पुलिस की कथित कार्रवाई पर तमाम तरह के सवाल जरूर उठे। पत्रकारों तथा तमाम मीडिया संगठनों ने समाचार पत्रों के वितरण में बाधा डालने की इस आपत्तिजनक कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है।

वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने सत्तारूढ आम आदमी पार्टी की सरकार पर प्रेस की आजादी पर हमला करने को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। इसे मीडिया पर हमला बताते हुए इसे पंजाब सरकार की ओर से लगाया गया अघोषित आपातकाल बताया गया। यह भी आरोप लगा कि भगवंत मान सरकार ने उसे परेशान करने वाली खबरों पर रोक लगाने के मकसद से पुलिस के जरिये यह दमनात्मक कार्रवाई की। यह घटना अभिव्यक्ति की आजादी पर ऐसा हमला है, जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें दोराय नहीं कि सीमावर्ती राज्य पंजाब की पाकिस्तान के साथ लगी इतनी लंबी सीमा है कि सुरक्षा के नजरिये से किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार को सतर्कता और पारदर्शिता के बीच बेहतर संतुलन बनाना चाहिए। रविवार को अखबार ले जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू करने से पहले मीडिया घरानों और समाचार पत्र आपूर्तिकर्ताओं सहित सभी हितधारकों को विश्वास में लिया जाना जरूरी था। निश्चित रूप से इससे व्यवधान और भ्रम की स्थिति से बचा जा सकता था। निर्विवाद रूप से मीडिया की स्वतंत्रता किसी स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है। यहां तक कि पंजाब के सबसे मुश्किल दौर में भी यह जरूरी है। सरकार और पुलिस को चरमपंथ के चरम वक्त को याद करने की सलाह दी जानी चाहिए, जब पुलिस सुबह के दौरे में साइकिल पर सवार हॉकरों को सुरक्षा प्रदान किया करती थी। उनकी सुरक्षा के साथ-साथ समाचार पत्रों के निर्बाध वितरण के लिये भी।

दो राज्य, अलग-अलग रास्ते

> पंजाब में राजनीतिक स्थिरता बहाल करने की फौरी जरूरत की खातिर वर्ष 1966 में इसका पुनर्गठन किया गया और हरियाणा का जन्म हुआ। 'द ट्रिब्यून' इस मील के पत्थर को याद करने और राज्यों की प्रगति को दिखाने के लिए एक साल भर चलने वाले धारावाहिक लेखों का सिलसिला शुरू कर रहा है।

वर्ष 1966 में पंजाब और हरियाणा के जन्म को याद करते हुए, मेरे विचार 1947 में हुए पंजाब के पहले विभाजन की ओर चले जाते हैं, जब भयानक सांप्रदायिक हिंसा, आगजनी, लूटपाट, बलात्कार और हत्याओं ने पूरे लाहौर को अपनी चपेट में ले लिया था, उस शहर में हमारा परिवार दशकों से बसा था। बंटवारे के बाद, हमें अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा और भारत की सरहद में पहुंचने से पहले अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ा। हालांकि, मरने वालों की सही संख्या का पता नहीं है, लेकिन अनुमान है कि 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग पांच गुना ज़्यादा बाशिंदे बेघर होकर शरणार्थी बन गए। नए देश को गंभीर समस्याएं निरंतर त्रस्त करती रहीं, सरकारी खजाना खाली था और पूर्वी पंजाब (बाद में पंजाब, भारत कहलाया) में अकाल जैसी स्थिति थी; सीमा पार करके आए लाखों-लाख लोगों के भोजन के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। अगले दो दशकों तक, पंजाब में एक के बाद एक बनी सरकारों ने, एक समर्पित नौकरशाही के मज़बूत समर्थन से, मानव इतिहास में शायद सबसे बड़े जबरन नागरिक पलायन के बाद पैदा हुई अनगिनत चुनौतियों का बखूबी सामना किया।रेडक्लिफ लाइन (जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय की) स्थापित होने से पहले, सिखों ने एक अलग होमलैंड की मांग उठाई। उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुईं। आज़ादी के बाद, शिरोमणि अकाली दल ने इस मांग को फिर से उठाने के लिए ज़ोरदार आंदोलन किया। यह देखते हुए कि भारत के अन्य राज्यों में पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था, पंजाबी भाषी राज्य की मांग कोई अपवाद नहीं थी। हालांकि, सिख समुदाय की राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ जुड़ने के बाद इसने कुछ अलग रंगत ले ली। राज्यों के भाषाई और प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठन की जांच के लिए गठित राज्य पुनर्गठन आयोग (1953-55) ने पंजाब के विभाजन को विशुद्ध भाषा के आधार पर करने को खारिज कर दिया। इसने पंजाब को द्विभाषी (पंजाबी और हिंदी) राज्य बनाए रखने का समर्थन किया।

The Tribune
PUNJAB, HARYANA MINISTRIES ANNOUNCED
WIDESPREAD DISTURBANCES IN ANDHRA: 3 KILLED IN POLICE FIRING
President's Rule To End Today
EARLY BIRD-2 FAILS TO MOVE INTO PROPER ORBIT
Panama Canal Swim
SPORTS FLASH
VISIT INDRA'S EXCLUSIVE SHOW ROOM FOR BINNY'S TEXTILES
THE UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED
(Regd. Office: 10-Brabourne Road, Calcutta)
Offers Its Heartiest Felicitations and Extends Sincere Assurances of Cooperation to the Three New States in all their Sphere of Activities leading to the Prosperity of their People.
I. P. GOENKA CHAIRMAN
L. R. SUNEJA ASST. GENERAL MANAGER
R. B. SHAH GENERAL MANAGER

सिखों के राजनीतिक प्रभुत्व का विरोध करने की गर्ज से पंजाब हिंदू महासभा ने शिरोमणि अकाली दल की पंजाबी सूबे की मांग का पुरज़ोर विरोध किया और पंजाब को हिंदी-बहुल राज्य बनाए रखने के लिए आंदोलन किया।

मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों, जोकि एक सक्षम किंतु अपने अधिनायकवादी रवैये के लिए जाने जाते नेता थे, उन्होंने अपने कार्यकाल (1956-64) के दौरान शिरोमणि अकाली दल और हिंदू महासभा के आंदोलनों से प्रभावी ढंग से निबटा। दिल्ली में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किसी भी ऐसे फैसले के खिलाफ थे जिसके परिणामस्वरूप हिंदू-सिख सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता हो। उक्त दोनों पक्षों के आंदोलन 1950 के दशक से लेकर 1960 के दशक तक चलते रहे, जब तक कि केंद्र सरकार भाषा के आधार पर पंजाब का फिर से गठन करने की मांग पर सहमत नहीं हो गई। साल 1966 में, पंजाब में 18 जिले थे, जिनमें से लगभग सात मुख्य रूप से हिंदी भाषी माने जाते थे: अंबाला, संगरूर, करनाल, गुड़गांव, रोहतक, हिसार और महेंद्रगढ़ के कुछ हिस्से। ऊपर बताए गए ग्रुप में, अंबाला (जो कि 1947 तक एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश छावनी थी) और करनाल को अपेक्षाकृत ज़्यादा विकसित माना जाता था क्योंकि वे ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक (जीटी) रोड पर स्थित थे। जबकि बाकी जिले तथाकथित भीतरी इलाकों में थे और 'पिछड़े' माने जाते थे। इन जिलों में नियुक्ति को सज़ा के तौर पर देखा जाता था, खासकर राजनीतिक रूप से जुड़े उन अधिकारियों के लिए जो सिर्फ अमृतसर, जालंधर और लुधियाना जैसे 'मेन लाइन' जिलों में ही काम करने के आदी थे, ये सभी जिले ऐन जीटी रोड पर स्थित थे। आम धारणा यह थी कि हरियाणा नामक पूरा इलाका 'पिछड़ा' है और इसे बाकी पंजाब से अलग करने से सिर्फ इसकी और उपेक्षा एवं गिरावट ही होगी।

केंद्र सरकार ने कैरों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अधिकार के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए जस्टिस एस.आर. दास आयोग बनाया था। इस आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद, 1964 के मध्य में, उभरते राजनीतिक माहौल ने कैरों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। जून 1964 में कैरों के जाने से राज्य प्रशासन के कामकाज पर असर पड़ा। एक और झटका तब लगा जब पाकिस्तान ने अगस्त 1965 में 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' शुरू कर दिया, जिसका मकसद जम्मू और कश्मीर में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित आतंकवादियों को भेजना था ताकि वहां अराजकता और अव्यवस्था फैलाई जा सके और घाटी पर कब्जा किया जा सके।

जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की नाकाम कोशिश एक बड़े पैमाने के युद्ध में बदल गई, जिसमें पंजाब युद्ध का मुख्य मैदान बन गया। पश्चिमी कमान की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को करारी हार दी। युद्ध का मुख्य मैदान होने के नाते, पंजाब इस संघर्ष से प्रभावित हुआ। 1965 की लड़ाई के बाद कुछ विवादों ने एक ऐसा राजनीतिक-सैन्य माहौल बनाया, जिसने मेरी याद्दाश्त में, पंजाब के पुनर्गठन को स्वीकार करने के केंद्र सरकार के फैसले को काफी हद तक प्रभावित किया।

शिरोमणि अकाली दल और हिंदू महासभा के लंबे समय तक चले आंदोलनों और, बाद में, 1965 के युद्ध ने पंजाब में बेचैनी और अनिश्चितता का माहौल बना डाला था, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था के कामकाज को भी प्रभावित किया था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री (जून 1964 - जनवरी 1966) और, बाद में, इंदिरा गांधी (1966-77 और 1980-84) दोनों ही पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में राजनीतिक स्थिरता को तुरंत बहाल करने की ज़रूरत को लेकर गंभीर रूप से चिंतित थे; उन्होंने भाषाई आधार पर इसके पुनर्गठन की ज़रूरत को स्वीकार किया। केंद्र सरकार का रुख तब साफ हो गया जब उसने मार्च 1966 में नए राज्यों की सीमाओं को तय करने और अन्य ज़रूरी सिफारिशें करने के लिए जस्टिस जे.सी. शाह कमीशन नियुक्त किया। शाह कमीशन की रिपोर्ट (मई 1966) ने सितंबर 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित होने का रास्ता साफ कर दिया।

इस अधिनियम के पारित होने के बाद, सभी आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं के अधिकारियों से उस कैडर की अपनी प्राथमिकता वाली पसंद बताने के लिए कहा गया जिनमें वे नियुक्त होना चाहते थे: पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। यह काम जल्दी पूरा हो गया। यह पक्का करने के लिए कि पुनर्गठन से जुड़े सभी मामले कुशलता, पारदर्शिता और निष्पक्षता से तय हों, जुलाई 1966 की शुरुआत में राज्य में यूनिटरी (एकात्मक) शासन लागू किया गया और पूर्व कैबिनेट सचिव और जाने-माने आईसीएस अधिकारी धर्म वीरा को पंजाब और हरियाणा का गवर्नर नियुक्त किया गया।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में शामिल थे: पंजाब (11 ज़िले, मुख्य रूप से पंजाबी बोलने वाले) और हरियाणा(सात ज़िले, मुख्य रूप से हिंदी बोलने वाले) नामक राज्यों का गठन; चार पहाड़ी ज़िलों और तीन अन्य ज़िलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश (तब एक केंद्र शासित प्रदेश)बनाना;चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करके एक केंद्र सरकार शासित प्रदेश रखना, जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में काम करेगा; सभी संपत्ति, राज्य की जमीन-जायदाद, देनदारियां और कर्ज 60:40 के अनुपात में बांटे जाएंगे; सिविल और पुलिस अधिकारियों को स्थानीयता (डोमिसाइल) और भाषा में दक्षता के आधार पर तीनों कैडर में बांटा जाएगा; विधायी सीटों के साथ-साथ संसद में प्रतिनिधित्व भी बांटा जाएगा; पंजाब हाईकोर्ट का नाम बदलकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया गया, जो दोनों नए राज्यों और चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश) के लिए काम करेगा; पंजाब यूनिवर्सिटी केंद्रीय व्यवस्था के तहत काम करती रहेगी; नदी जल, पावर बोर्ड आदि से संबंधित मामले अंतर-राज्यीय निकायों द्वारा संचालित किए जाएंगे; हर राज्य का अपना गवर्नर होगा।

प्रेरणा

विपत्ति में छिपा वरदान: जब दुख बन जाता है ईश्वर का संदेश

जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है, जिसमें सुख और दुख दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि सुख ही वरदान है और दुख अभिशाप। परंतु सच्चाई इससे कहीं गहरी है। कई बार जो परिस्थिति हमें विपत्ति जैसी लगती है, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख और परिवर्तन का कारण बनती है। यह बात महाराज दशरथ और सुग्रीव के जीवन से गहराई से समझी जा सकती है।

अयोध्या के महाराज दशरथ, जिनका जीवन वैभव, समृद्धि और यश से भरा था, उनके हृदय में एक ही कमी चुभती थी—संतान की। वे राजा थे, लेकिन बिना वारिस के उनका राज्य अधूरा था। वे हर यज्ञ, हर उपाय कर चुके थे, फिर भी पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला था। यही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। परंतु इस अंधकार में भी उनके भीतर एक दीपक जलता था—श्रवण कुमार के पिता का दिया हुआ श्राप।

कहते हैं, एक बार दशरथ वन में शिकार खेलने गए थे। संध्या का समय था, झील के किनारे से जल पीने की आवाज आई, और उन्होंने यह सोचकर बाण चला दिया कि कोई पशु होगा। लेकिन वह आवाज किसी पशु की नहीं, बल्कि एक युवक की थी—श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माता-पिता के लिए जल भरने गया था। जब दशरथ वहां पहुंचे, तो यह जानकर उनके हृदय पर वज्र गिरा कि उन्होंने एक निर्दोष

ब्राह्मण बालक की हत्या कर दी।

श्रवण के माता-पिता ने जब यह सुना, तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने दशरथ को श्राप दिया—"जैसे मैं अपने पुत्र-वियोग में तड़प-तड़पकर प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही तू भी अपने पुत्र-वियोग में तड़पकर मरेगा।" यह वाक्य सुनते ही दशरथ स्तब्ध रह गए। परंतु वर्षों बीत जाने के बाद, जब वे संतान-सुख से वंचित रहे, तो उन्हें उस श्राप में आशा की एक किरण दिखी। उन्होंने सोचा—"यदि मुझे पुत्र-वियोग में मरना है, तो इसका अर्थ है कि मुझे पुत्र अवश्य मिलेगा।" इस प्रकार जो श्राप था, वही उनके लिए भविष्य का वरदान बन गया। यही तो जीवन का रहस्य है—जहां हम अंत समझते हैं, वहीं से नई शुरुआत होती है।

इसी तरह सुग्रीव की कहानी भी हमें बताती है कि विपत्ति व्यक्ति को निखार देती है। जब बाली ने अन्यायपूर्वक उसे राज्य से निष्कासित कर दिया, तब सुग्रीव अकेला, भयभीत और असहाय था। वह अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों, नदियों, वनों और द्वीपों में भटकता रहा। उसने पृथ्वी के हर कोने को देखा, हर भूखंड की जानकारी ली। उस समय उसे यह ज्ञान निरर्थक लगता था—वह केवल अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहा था। लेकिन जब भगवान श्रीराम ने माता सीता की खोज का दायित्व सुग्रीव को सौंपा, तब वही अनुभव अमूल्य बन गया।

सुग्रीव ने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर वानरों को सही दिशा दी, उन्हें बताया कि कौन-से प्रदेशों में खोज करनी चाहिए। अंततः उसी भौगोलिक ज्ञान के कारण हनुमान जी को माता सीता का पता मिला। यह सब उसी विपत्ति का परिणाम था, जो कभी उसके लिए दुख का कारण थी। यही कारण है कि कहा गया है—"अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान हैं।"

मनुष्य जब सुख में होता है, तो वह आत्मसंतुष्ट हो जाता है। परंतु जब दुख आता है, तब वह भीतर झांकना शुरू करता है, आत्मबल की खोज करता है और निखर जाता है। यही दुख उसे जीवन के उच्चतम सत्य तक पहुंचाता है। हर विपत्ति के भीतर ईश्वर का कोई संकेत छिपा होता है। जो उस संकेत को पहचान लेता है, वही जीवन का सच्चा साधक बन जाता है।

इसलिए, जब जीवन में सुख मिले, तो कृतज्ञ रहें—और जब दुख आए, तो घबराएं नहीं। क्योंकि वही दुख, वही संघर्ष, वही कठिनाई आपके जीवन में किसी बड़े वरदान का द्वार खोल रही होती है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता; बस वह हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए कभी-कभी कांटों से भरा रास्ता दिखाता है। इसलिए जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर के संकेत को समझ लेता है, वही सच्चा पुरुषार्थी कहलाता है। विपत्ति जीवन की परीक्षा नहीं, बल्कि उसका वरदान है—एक ऐसा वरदान जो हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाता है, जहां केवल आत्मा की ज्योति शेष रह जाती है और व्यक्ति समझ जाता है कि हर दर्द के पीछे भी भगवान की करुणा ही छिपी है।

वादे और दावे के बीच झूलती बिहार की राजनीति

बिहार में चुनावी घमासान की हवा चल रही है। प्रमुख राजनीतिक दल इस हवा के रुख को अपनी ओर मोड़ने का जी तोड़ प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई भी ऐसी आश्वस्ति पीलिक्षित नहीं हो रही है कि हवा किस ओर बह रही है। राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे दावे और वादे सत्ता की राह को आसान बनाने की मात्र कवायद ही कही जा सकती है। बिहार की राजनीति में चार प्रमुख राजनीतिक दल जोर लगा रहे हैं, बाकी के सभी इनके सहारे सत्ता का स्वाद चखने के लिए लालायित हैं। यह प्रमुख दल अपने ही दल के अंदर उठ रहे भीतरघात के लावे से परेशान हैं। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है तो उनके घर के अंदर से ही विरोध की चिंगारी सुलग रही है। जो भविष्य में बड़ी आग का रूप भी ले सकती है। तेजप्रताप यादव नए दल के साथ चुनावी मैदान में उतरकर तेजस्वी के सपनों को मिटाने का अभियान छेड़े हुए हैं, वहीं उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के शासन करने का अंदाज एक बड़ी चुनौती बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से इसी को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार को विकास चाहिए या फिर जंगलराज चाहिए। लालू प्रसाद यादव के शासन बारे में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इस आशय की टिप्पणी की गई थी कि बिहार में जंगलराज है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अपनी सरकार के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए राजद के पास केवल भाजपा का विरोध करना ही प्रचार करने का एक मात्र विकल्प है। यह वोट प्राप्त करने का माध्यम तो बन सकता है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से नकारात्मक राजनीति का पर्याय ही माना जाएगा। नकारात्मक राजनीति किसी भी प्रकार से उचित नहीं मानी जा सकती। बिहार की राजनीति में वोट चोरी का मामला भी जोर शोर से उठाया गया। इसका लाभ भी विपक्ष उठा सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को उठाने में विपक्ष ने जल्दबाजी कर दी। चुनाव आयोग की ओर से वोट चोरी के बोर में पक्ष रखने के बाद यह मुद्दा गहरी खाई में समा गया। कांग्रेस और राजद की ओर से जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, वह यही संकेत करती है कि इनको सत्ता प्राप्त करने की जल्दी है। हमारे देश में एक कहावत तो सबने सुनी ही होगी कि जल्दी फायदा कम, नुकसान ज्यादा करती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती का परिणाम सभी देख चुके हैं। अब बिहार में राहुल और तेजस्वी एक साथ हैं। राजनीतिक वातावरण में हमेशा से यही प्रचलित धारणा बनी हुई है कि दुश्मन का दुश्मन भी एक दोस्त की तरह ही होता है। कांग्रेस, भाजपा को राजनीतिक विरोधी ही मानती है, इसके साथ ही राजद के विचार भी भाजपा के विपरीत ही हैं। इसलिए बिहार में आज कांग्रेस और राजद एक साथ हैं। विपक्ष की ओर से राजद के नेता तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया है। उन पर परिवारवाद की राजनीति का तमगा भी लगा है। इसके कारण भी राजद के अन्य वरिष्ठ नेता मैदान में खुलकर नहीं आ रहे हैं। राजद के कई नेताओं का अंदाज तेज प्रताप को समर्थन देने जैसा ही है। इस प्रकार की राजनीति भितरघात की श्रेणी में आएगी। अगर बिहार में तेजप्रताप अपना राजनीतिक कौशल दिखा पाते हैं तो यह स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि फिर तेजस्वी की राह कांटों भरी ही होगी। दोनों भाइयों के बीच यह राजनीतिक घमासान मात्र नेतृत्व की ही लड़ाई है। यह भी सबको समझ में आ रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का चुनावी मैदान में आना राजनीतिक सौदेबाजी करने जैसा ही माना जा रहा है। प्रशांत किशोर जितना जोर दिखाएंगे, उतना ही वह बिहार की राजनीति को प्रभावित करेंगे। यह प्रभाव किसके लिए खतरा बनेगा, यह अभी से कह पाना संभव नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति स्थिति को देखकर यही कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का फोकस उन वोटों पर अधिक है, जो राजद या कांग्रेस को मिलते हैं। कर्पूरी ठाकुर के परिजन को अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाना भी संभवतः इसी रणनीति का ही हिस्सा है। जहां तक भाजपा और नीतीश कुमार की जदयू की बात है तो यही कहा जा सकता है कि यह दोनों ही विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार को विकास की जरूरत भी है। भाजपा और जदयू को लगता है कि विकास के नाम पर उसे फिर से सत्ता प्राप्त हो जाएगी। इसके विपरीत विपक्ष की ओर से कांग्रेस और राजद की ओर से आम जन के निजी स्वार्थों को कुरेदकर उनको आर्थिक लाभ देने के वादे किए जा रहे हैं। ऐसे वादे लोग को त्वरित लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। नौकरियां देना भी असंभव है, इसलिए स्वरोजगार देने का प्रयास करना चाहिए। केन्द्र सरकार इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। जिसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। कई लोगों ने अपना जीवन स्तर भी सुधारा है। युवाओं को नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। बिहार के युवा इस बारे में सोचें, यही बिहार की राजनीति का आधार बने। राजनीतिक दलों को इस बारे में भी सोचना चाहिए। राजनीति को जन भावनाओं के अनुसार ही होना चाहिए। इसके लिए परिवारवाद नहीं, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हर राजनीतिक दल को प्रयास करना चाहिए। हालांकि हमारा आशय परिवार के सहारे राजनीति में कदम रखने वाले राहुल और तेजस्वी के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़े करने का नहीं है। हो सकता है कि वे देश की भावी राजनीति के सूत्रधार बनें, लेकिन फिलहाल उनके खाते में ऐसी कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, जिसके आधार पर उनका राजनीतिक आंकलन किया जाए। विपक्ष की दूसरी कठिनाई यह है कि इनके पास प्रचार करने वाले जमीनी नेताओं की कमी है, जबकि भाजपा और जदयू में ऐसे नेताओं की लम्बी सूची है। जिसके कारण यह सभी जगह अपना प्रचार करने की योजना बना सकते हैं। अब देखना यह है कि बिहार की जनता किसको पसंद करेगी और किसको नापसंद, यह आने वाले समय में पता चल जाएगा।

अभियान

शिव विषपान की भूमि में मौन प्रकृति: हिमालय की गोद में छिपा केदारताल का दिव्य रहस्य

जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल वायु की शीतल ध्वनि, हिम के कणों की चमक और जल की लहरों की धीमी गति रह जाती है — वहीं से अध्यात्म की सच्ची अनुभूति आरंभ होती है। ऐसे ही मौन और दिव्य स्थानों में से एक है उत्तरकाशी के ऊंचे पर्वतों के बीच बसा केदारताल, जिसे लोकश्रुति में शिव का ताल कहा गया है। यह झील केवल हिमालय की एक प्राकृतिक झील नहीं है, बल्कि यह उस स्थिरता, त्याग और तप की प्रतीक है, जो स्वयं भगवान शिव के स्वरूप में समाहित है।

समुद्र तल से लगभग साढ़े चार हजार मीटर की ऊँचाई पर स्थित यह पवित्र झील थलय सागर, मेरु और भृगुपंथ जैसे दिव्य शिखरों की गोद में स्थित है। चारों ओर हिमाच्छादित चोटियाँ हैं, जिनके बीच यह झील एक दर्पण की तरह चमकती है, मानो स्वयं आकाश इसमें उतर आया हो। यहाँ तक पहुँचने वाला प्रत्येक यात्री महसूस करता है कि वह पृथ्वी पर नहीं, किसी देवलोक में प्रवेश कर गया है। हिम की ठंडी हवा जब चेहरे को छूती है, तो वह केवल ठंडक नहीं देती, बल्कि भीतर की अग्नि को भी शांत कर देती है।

पुराणों में वर्णन है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उससे अमृत के साथ-साथ कालकूट विष भी निकला। वह विष इतना प्रचंड था कि सम्पूर्ण सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हो गया। उस समय देवों और असुरों ने एकमात्र त्रिदेवों में से शिव को पुकारा — क्योंकि केवल वे ही उस विष की अग्नि को सह सकते थे। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण किया। उस तप से उनका कंठ नीला पड़ गया, और वे 'नीलकंठ' कहलाए। किंवदंती यह कहती है कि उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए उन्होंने हिमालय की गोद में स्थित इस झील का पवित्र जल पिया। उसी क्षण यह झील केदारताल के नाम से पूजनीय बन गई, और तब से यह स्थान शिव के ध्यान का प्रतीक माना जाता है।

केदारताल के चारों ओर का विस्तार जितना भव्य है, उतना ही रहस्यमय भी। यहां न कोई नगरीय कोलाहल है, न कोई बाज़ार, न मनुष्य की चहल-पहल। केवल हिमाच्छादित पर्वत, नीले आकाश का अथाह विस्तार और मौन में गूंजती हुई वायु की नादमयी ध्वनि। ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव के ध्यान में लीन हो। यह वह भूमि है जहां शून्यता भी संगीत बन जाती है, और मौन भी संवाद।

केदारताल केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और भौगोलिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। यह झील थलय सागर हिमनद के पिघलने से बनती है और इसी से 'केदार गंगा' नामक नदी का उद्गम होता है, जो आगे चलकर भागीरथी से मिलती है। यह संगम न केवल जल का मेल है, बल्कि तप और करुणा का संगम भी है।

यहां तक पहुंचने की यात्रा कठिन है, परंतु उसी कठिनाई में इस स्थल का सौंदर्य छिपा है। गंगोत्री से लगभग 20 किलोमीटर का यह ट्रेक हिमालय की सबसे चुनौतीपूर्ण यात्राओं में से एक माना जाता है। मार्ग में पत्थरों की ढलानें, बर्फ की परतें और ठंडी हवाओं की तीखी लहरें हर यात्री की परीक्षा लेती हैं। गंगोत्री (3100 मीटर) से यात्रा शुरू होती है और तीन से चार दिनों के कठिन आरोहण के बाद केदारताल के दर्शन होते हैं। वहां पहुंचने के बाद यात्रियों को ऐसा अनुभव होता है मानो समय ठहर गया हो — न कोई भय, न कोई लालसा, केवल शांति और एकाग्रता।

स्थानीय पुजारी और साधक बताते हैं कि यह झील केवल दर्शन का स्थल नहीं, बल्कि आत्म-संयम का विद्यालय है। यहां प्रकृति का हर तत्व शिव के किसी न किसी गुण का प्रतीक बन जाता है। बर्फ उनके धैर्य की प्रतीक है, जल उनके करुणा का, और मौन उनके ज्ञान का। जो व्यक्ति यहां कुछ समय ध्यान में बैठता है, उसे अपने भीतर वही स्थिरता अनुभव होती है, जो शिव की समाधि में दिखाई देती है।

इस स्थल की दार्शनिक व्याख्या आधुनिक युग के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। आज मानव विज्ञान और तकनीक के शिखर पर पहुँच चुका है, परंतु भीतर से अधिक अस्थिर और बेचैन है। हमने भौतिक सुख तो प्राप्त कर लिए, परंतु मानसिक शांति खो दी। हमने प्रकृति को संसाधन मानकर उसका दोहन किया, किंतु भूल गए कि यही प्रकृति हमारी आत्मा की दर्पण है। केदारताल हमें यह संदेश देता है कि जब तक हम अपने भीतर संतुलन नहीं लाते, तब तक बाहरी प्रगति अधूरी रहेगी।

शिव का विषपान केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक प्रतीक है — जीवन के उस दायित्व का, जिसमें हमें संसार के विष यानी दुख, प्रदूषण, लोभ, हिंसा और असंतुलन को अपने भीतर रूपांतरित करना है। जैसे शिव ने उस विष को करुणा में बदल दिया, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी लालसाओं, स्वार्थ और अज्ञान के विष को ज्ञान, सेवा और प्रेम में बदलना होगा। यही 'शिवत्व' का सच्चा अर्थ है।

जब कोई व्यक्ति केदारताल की ओर देखता है, तो उसे केवल एक झील नहीं दिखाई देती, बल्कि स्वयं शिव की निःशब्द उपस्थिति का अनुभव होता है। हिम से ढकी पर्वत-श्रृंखलाएं उस ध्यान की परिधि बन जाती हैं, और झील का शांत जल उस ध्यान की गहराई। यह वह स्थान है जहां प्रकृति और अध्यात्म एकाकार हो जाते हैं।

आज जब पृथ्वी प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानसिक तनाव से जूझ रही है, तब केदारताल का संदेश पहले से अधिक अर्थपूर्ण हो गया है। यह हमें याद दिलाता है कि संतुलन बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर के संयम और समर्पण से उत्पन्न होता है। यदि मानव अपने भीतर के 'विष' को पहचान ले और उसे शिव की तरह धारण कर सके, तो वह स्वयं भी नीलकंठ बन सकता है — वह जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं तप करता है।

इसलिए केदारताल केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। जब कोई वहां पहुंचता है, तो वह बाहरी ऊंचाइयों के साथ-साथ अपनी आंतरिक ऊंचाई को भी छू लेता है। वहां का मौन हमें यह सिखाता है कि सत्य किसी शोर में नहीं, बल्कि मौन में प्रकट होता है।

केदारताल के नीले जल में जब हिम की परछाई उतरती है, तो वह दृश्य केवल सुंदर नहीं, बल्कि ध्यानमग्न होता है — मानो स्वयं शिव उस जल में निहित हों। यही उस भूमि का रहस्य है, जहां विष भी अमृत बन जाता है, और मौन भी ईश्वर की वाणी बनकर गूंजता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग के 'री-इमेजिंग एग्रीकल्चर : अ रोडमैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन' का अनावरण किया

देश के कृषि क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने में नीति आयोग का रोडमैप महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी एवं कृषि राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा की प्रेरक उपस्थिति

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- इस रोडमैप में डेटा कनेक्टिविटी तथा इंटेलिजेंस को सीधे कृषि व्यवस्था में एकीकृत करने का विजन प्रस्तुत किया गया है
- इस रोडमैप के मुख्य दिशानिर्देश कृषि क्षेत्र में गुजरात के विजन के साथ पूर्णतः सुसंगत हैं
- नीति आयोग की महत्वपूर्ण पहलों को साकार करने में गुजरात ने अग्रणी भूमिका अदा की है
- गुजरात ने भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप फसल विविधीकरण तथा टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन दिया है
- राज्य सरकार ने टेक्नोलॉजी तथा मॉडर्न टूल्स की सहायता से खेती को अधिक उत्पादक बनाने की दिशा में अनेक प्रोत्साहक कदम उठाए हैं

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग के नीति फ्रंटियर टेक हब द्वारा तैयार किया गया 'री-इमेजिंग एग्रीकल्चर : अ रोडमैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन' सोमवार को लॉन्च करते हुए कहा कि देश के कृषि क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने का यह रोडमैप एक महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट है।

श्री पटेल ने आगे कहा कि किसानों के हित में टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने के लिए नीति आयोग के राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट का आज गुजरात की भूमि से अनावरण हुआ है। यह राज्य के लिए गौरव का विषय है। इतना ही नहीं; यह रोडमैप टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट के माध्यम से अन्नदाता के सपने साकार करने का आधार बनेगा।

उन्होंने कहा कि इस रोडमैप में टेक्नोलॉजी को केवल मशीनरी तक सीमित न रखते हुए डेटा कनेक्टिविटी तथा इंटेलिजेंस को सीधे कृषि व्यवस्था में एकीकृत करने का विजन रखा गया है। उन्होंने यह मत भी व्यक्त किया कि इस रोडमैप के मुख्य दिशानिर्देश कृषि क्षेत्र में गुजरात के विजन के साथ पूर्णतः सुसंगत हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब, युवा, अन्नदाता तथा नारी शक्ति – ग्यान को विकसित भारत के चार स्तंभ बताया है। यह रोडमैप उनमें से एक स्तंभ यानी अन्नदाता को समर्पित है और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने नीति आयोग की महत्वपूर्ण पहलों को साकार करने में गुजरात के अग्रणी भूमिका निभाने का उल्लेख करते हुए कहा कि नीति आयोग के मार्गदर्शन में आज देश में जो चार ग्रोथ हब विकसित किए जा रहे हैं, उनमें सूरत इकोनॉमिक रीजन भी शामिल है। इस रीजन के 6 जिलों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने की शुरुआत हो गई है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि नीति आयोग के पैटर्न पर गुजरात ने भी राज्य स्तर पर एक थिंक टैंक 'गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन' यानी ग्रिट की स्थापना की है। उन्होंने इसका उल्लेख करते हुए आगे कहा कि ग्रिट के माध्यम से गुजरात ने राज्य के 6 आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान भी लॉन्च किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त; प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत@2047 विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने सशक्त रोडमैप विकसित गुजरात@2047 तैयार किया है। उसमें भी नीति आयोग के बहुमूल्य सुझावों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी तथा मशीनीकरण को व्यापक बनाकर कृषि विकास किया गया होने की भूमिका भी रखी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात ने भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तथा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (फसल विविधीकरण व टिकाऊ कृषि) को प्रोत्साहन दिया है। टेक्नोलॉजी तथा मॉडर्न टूल्स की सहायता से खेती को अधिक प्रोडक्टिव (उत्पादक) बनाने की दिशा में अनेक प्रोत्साहक कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान फॉर एग्रीकल्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा फार्मर रजिस्ट्री जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर अंतर्गत किसानों को राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ मिलें; इसके लिए ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान सुविधा प्रदान करने हेतु आई-पोर्टल विकसित किया गया है।

उन्होंने कहा कि डिजिटल एग्रीकल्चर को अधिक सफल बनाने के लिए गुजरात ने एक डेडिकेटेड डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजी की सहायता से भूमि की उपज क्षमता, फसल में होने वाले रोग एवं पोषक तत्वों की जानकारी अब अधिक तेजी से प्राप्त हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन सीड्स, इक्विपमेंट टूल्स तथा इनपुट्स में नवीनता लाकर खेती में लागत खर्च कम घटाने तथा पर्यावरणीय हानि से बचने के प्रयास भी हो रहे हैं।

इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) श्री बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम, प्रतिष्ठित सदस्य श्री देब जानी घोष तथा कार्यक्रम निदेशक डॉ. नीलम पटेल ने प्रासंगिक संबोधन में गुजरात की कृषि प्रगति एवं टेक्नोलॉजिकल फार्मिंग तथा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की प्रशंसा की।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, कृषि विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. अंजू शर्मा, एटीई चंद्र फाउंडेशन के सह-संस्थापक श्री अमित चंद्र तथा उच्चाधिकारी एवं आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं जयपुर के बीच चलाएगी स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस एवं जयपुर स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार हैः

1. ट्रेन संख्या 09730/09729 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09730 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर स्पेशल बुधवार, 05 नवंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 09:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 06:45 बजे जयपुर पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09729 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल मंगलवार, 04 नवंबर, 2025 को जयपुर से 08:10 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:55 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, मांडल, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर और किशनगढ़ स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच हैं।

ट्रेन 09730 की बुकिंग 04 नवम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर–ओखा एक्सप्रेस 04 एवं 05 नवंबर को द्वारका स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी

रेलवे प्रशासन द्वारा ओखा स्टेशन पर एल.सी. संख्या 313 के एल.एच.एस. पर गर्डर लॉन्चिंग कार्य किए जाने के कारण दिनांक 05 एवं 06 नवंबर, 2025 को आवश्यक इंजीनियरिंग कार्य किया जाएगा। इस कार्य के मद्देनज़र, कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट एवं शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि —

ट्रेन संख्या 19209 भावनगर–ओखा एक्सप्रेस दिनांक 04 एवं 05 नवंबर, 2025 को द्वारका स्टेशन पर ही समाप्त होगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस दिनांक 05 एवं 06 नवंबर, 2025 को द्वारका स्टेशन से ही प्रारंभ होगी।

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे उक्त तिथियों में अपनी यात्रा से पूर्व गाड़ियों की स्थिति एवं समय संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए NTES ऐप अथवा भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करें।

आरक्षित यात्रियों को इस परिवर्तन की सूचना SMS अलर्ट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। रेलवे प्रशासन यात्रियों से सहयोग की अपील करता है एवं किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है।

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के परिवारजनों ने 'राष्ट्रीय एकता दिवस' पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गत गुरुवार, 30 अक्टूबर, 2025 को गुजरात के एकता नगर में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के परिवार के सदस्यों से शिष्टाचार मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एकता नगर में भारत सरकार और गुजरात सरकार के सहयोग से 'राष्ट्रीय एकता दिवस' का भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। इस वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार साहब के परिजन राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए एकता नगर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा, वे राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम देखा।

सरदार साहब की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता नगर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पहुंचे सरदार पटेल के परिजन

"स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के जरिए मोदी जी ने दुनिया को दिखाया कि एक और अखंड भारत क्या करने में सक्षम है"

सरदार साहब के पौत्र श्री गौतम पटेल और उनका परिवार पहुंचा एकता नगर

सरदार वल्लभभाई पटेल के पौत्र श्री गौतम डाह्याभाई पटेल (उम्र 80वर्ष), उनकी पत्नी डॉ. नंदिता गौतमभाई पटेल (उम्र 79 वर्ष), श्री गौतमभाई पटेल के पुत्र यानी सरदार साहब के प्रपौत्र श्री केदार गौतमभाई पटेल (उम्र 47 वर्ष), उनकी पत्नी श्रीमती रीना केदार पटेल (उम्र 47 वर्ष) तथा केदारभाई और रीनाबेन की पुत्री कु. करीना केदार पटेल (उम्र 13 वर्ष) राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एकता नगर पहुंचे थे। इसके अलावा, श्री गौतमभाई पटेल के चचेरे भाई श्री समीर इंद्रकांत पटेल (उम्र 68 वर्ष) तथा उनकी पत्नी श्रीमती रीता समीर पटेल (उम्र 66 वर्ष) भी इस अवसर पर मौजूद रहे। उन्होंने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उनके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। 31 अक्टूबर, 2025 को सरदार पटेल के परिवारजन राष्ट्रीय एकता दिवस के भव्य समारोह में शामिल हुए।सरदार साहब के परिवार के सदस्यों ने 1 नवंबर, 2025 को दुनिया की सबसे ऊंची सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। प्रतिमा को देखकर सरदार साहब के परिवारजनों ने गर्व का अनुभव किया और उन्होंने सरदार साहब को इतनी अद्भुत श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। सरदार साहब के पौत्र श्री गौतमभाई पटेल ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विजिटर्स बुक में अंग्रेजी भाषा में शुभकामना संदेश भी लिखा है, जिसके नीचे परिवार के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह संदेश निम्नानुसार है :

"स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यह यात्रा वास्तव में प्रेरणादायी रही है। यह प्रतिमा इंजीनियरिंग, डिजाइन और निर्माण का एक अद्भुत प्रदर्शन है। मैं और मेरा परिवार पीएम मोदी जी, और सरदार पटेल को इस श्रद्धांजलि को मूर्तिमंत करने में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के बहुत आभारी हैं। यहां हमने विभिन्न स्थलों का दौरा किया तथा सरदार साहब के जीवन एवं उनके जीवन आदर्शों के प्रभावों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो हमारी यादों में सदैव जीवंत रहेगी। मैं एकता नगर में पर्यटन क्षेत्र में हुई प्रगति तथा यहां चलने वाली शैक्षणिक एवं मनोरंजक गतिविधियों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूं। गुजरात राज्य का इतिहास और संस्कृति काफी समृद्ध है, और ऐसा एक स्थान होना ही चाहिये, जहां आपको प्रकृति के साथ तल्लीन होने का एक अद्भुत पर्यटन अनुभव मिल सके। यहां देखने और जानने लायक काफी कुछ है और बहुत जल्द ही हम यहां दोबारा आएंगे। हम पीएम मोदी जी और यहां के सभी लोगों का उनके समर्पण भाव के लिए आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने विश्व को दिखाया है कि एक और अखंड भारत क्या करने में सक्षम है!"

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल बेमौसम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के साथ खड़े रहे

मुख्यमंत्री ने गीर सोमनाथ तथा जूनागढ जिलों के गाँवों में स्वयं जाकर फसल नुकसान के स्थल-स्थिति का निरीक्षण किया, धरतीपुत्रों की व्यथा संवेदनापूर्वक सुनी

राज्य में बेमौसम वर्षा से कृषि फसलों को हुए नुकसान का मुख्यमंत्री के दिशानिर्देश में युद्ध स्तर पर सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया

राज्य के लगभग 70 प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, 4800 से अधिक टीमें सर्वेक्षण कार्य में जुड़ीं

शेष प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के लिए समग्र प्रशासन 24X7 कार्यरत है

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- किसानों पर आन पड़ी विपदा में राज्य सरकार पूरी संवेदना के साथ खड़ी है
- अति शीघ्र राहत पैकेज घोषित कर किसानों को नुकसान से तेजी से उबारने की प्रतिबद्धता

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई बेमौसम बारिश से राज्य के अनेक किसानों की फसलों को हुए व्यापक नुकसान के रूप में आई अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा के समय पूरी संवेदना के साथ राज्य के किसानों के साथ खड़े रहकर नुकसान के सर्वेक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कराया है।

श्री पटेल ने इस उद्देश्य से गांधीनगर से रीयल टाइम मॉनिटरिंग कर तथा उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित कर राज्य के किसानों को हुए नुकसान की जानकारी हासिल की थी और किसानों की फसलों को हुए व्यापक नुकसान की पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए थे।

इस संदर्भ में कृषि विभाग सहित राज्य सरकार के अन्य विभागों ने समन्वय स्थापित कर प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और अब तक लगभग 70 प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। शेष क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री के दिशादर्शन में कृषि विभाग सहित सम्बद्ध विभाग 24X7 कार्यरत हैं।

इस बेमौसम बरसात के कारण कृषि फसलों में हुए नुकसान के चलते किसानों को अधिक से अधिक तेजी से सहायता मिल सके; इसके लिए प्रभावित जिलों में 4800 से अधिक टीमों द्वारा सर्वेक्षण कार्य युद्ध स्तर पर किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सोमवार दोपहर बाद स्वयं गीर सोमनाथ जिले के कडवासण तथा जूनागढ जिले के पाणीद्रा गाँव पहुँचे और उन्होंने किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को हुए नुकसान का मौके पर जायजा लिया तथा किसानों की व्यथा सहानुभूतिपूर्वक सुनी।

मुख्यमंत्री के साथ मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया, डॉ. प्रद्युमन वाजा तथा राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया भी इन प्रभावित क्षेत्रों के स्थल निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने धरतीपुत्रों को सांत्वना देते हुए कहा कि समग्र सरकार उनके साथ पूरी संवेदना के साथ खड़ी है और किसानों को नुकसान से तेजी से उबार कर स्थिति पूर्ववत करने की प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत है।

उन्होंने कहा कि प्राथमिक अनुमान के अनुसार हाल की बेमौसम बारिश में राज्य में 249 तहसीलों के 16 हजार से अधिक गाँवों की कृषि फसलों को नुकसान हुआ है। इसमें 70 प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है, जबकि शेष क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस नुकसान का सर्वेक्षण होते ही अति शीघ्र समय में उदारतम राहत सहायता पैकेज घोषित करने की दिशा में जरूरी प्रक्रिया भी तत्परता के साथ शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर फसलों को हुए नुकसान तथा समग्र स्थिति का जायजा लिया है। उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी सूरत, कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी भावनगर, आदिजाति विकास मंत्री श्री नरेश पटेल तापी, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा जूनागढ तथा गीर सोमनाथ और राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया अमरेली जिले का दौरा कर किसानों के दुःख में सहभागी हुए।

माननीय रेलमंत्री ने अहमदाबाद स्टेशन का दौरा किया,अहमदाबाद स्टेशन पुनर्विकास एवं हाई स्पीड रेल परियोजना के प्रगति की समीक्षा की

(जीएनएस)। माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने दिनांक 03.11.2025 को अहमदाबाद स्टेशन का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने अहमदाबाद स्टेशन पर चल रहे स्टेशन पुनर्विकास कार्यों तथा हाई स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना के प्रगति की समीक्षा की।

माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद स्टेशन पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया और इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भारत में यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देशभर में स्टेशनों का व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है। वर्तमान में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है, जिनमें अहमदाबाद स्टेशन एक प्रमुख स्टेशन है।

श्री वैष्णव ने बताया कि अहमदाबाद स्टेशन पर 16 मंज़िला आधुनिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। सरसपुर साइड पर बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है तथा अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल स्टेशन लगभग पूर्णता की ओर है। बुलेट ट्रेन स्टेशन और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को आपस में एकीकृत (इंटीग्रेटेड) रूप से विकसित किया जा रहा है, सरसपुर साइड मेट्रो स्टेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा यात्रियों के लिए खोला जा चुका है।

उन्होंने आगे बताया कि अहमदाबाद स्टेशन को तीन अतिरिक्त प्लेटफॉर्म प्राप्त होंगे, जिससे स्टेशन की ट्रेनों की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। स्टेशन को शहर के दोनों ओर कालूपुर और सरसपुर साइड आधुनिक स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। सभी प्लेटफॉर्म कोंकर्स रूफ प्लाज़ा से कवर हो जाएंगे तथा स्टेशन पर एलीवेटेड रोड का कार्य भी तीव्र गति से जारी है। इस प्रकार शहर के दोनों छोर कोंकोर्स,एलेवेटेड रोड, फूटओवर ब्रिज से जुड़ जाएगा। मंत्री महोदय ने बताया कि पिछली बार जब उन्होंने परियोजना का निरीक्षण किया था, तब बेसमेंट का कार्य प्रगति पर था, अब दो अंडरग्राउंड बेसमेंट एवं ग्राउंड फ्लोर का कार्य पूर्ण हो गया है जबकि चौथी मंज़िल तक का स्ट्रक्चर फ्रेम तैयार हो चुका है।

देश के प्रमुख 20 स्टेशनों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद से नई ट्रेनों की डिमांड अधिक आती है। गुजरात में अहमदाबाद और सूरत से से अधिक मांग रहती है। इस बढ़ती डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की परिचालन क्षमता बढ़ाने हेतु अहमदाबाद के वटवा में एक मेगा टर्मिनल विकसित किया जाएगा, जिसमें 10 पिट लाइनों का निर्माण होगा। इसके माध्यम से लगभग 45 अतिरिक्त ट्रेनों की केपेसिटी बढ़ेगी जिससे अहमदाबाद से लगभग 150 ट्रेनों का संचालन संभव हो पाएगा।

अहमदाबाद स्टेशन का पुनर्विकास कार्य विरासत स्मारकों को आधुनिक शहरी केंद्र के साथ एकीकृत करने की अवधारणा पर आधारित है। यह परियोजना एक विश्वस्तरीय मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) का निर्माण करेगी, जिसमें पर्याप्त पार्किंग, कालूपुर आरओबी और सारंगपुर आरओबी को जोड़ने वाला एलिवेटेड रोड नेटवर्क, लैंडस्केप्ड प्लाज़ा, कॉनकोर्स एरिया तथा उन्नत यात्री सुविधाएं सम्मिलित होंगी।

स्टेशन का वास्तुशिल्प डिजाइन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है, जो सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सौंदर्य का सुंदर समावेश प्रदर्शित करेगा। कालूपुर साइड स्थित आइकॉनिक एमएमटीएच टॉवर अहमदाबाद के वास्तु परिदृश्य का नया प्रतीक बनेगा। एएसआई संरक्षित 'ईंट (ब्रिक्स) मीनार' और 'झूलता मीनार' को भी पुनर्विकास योजना में समाहित किया जाएगा। यह स्टेशन राष्ट्रीय हाई-स्पीड रेल टर्मिनल, मेट्रो और बीआरटीएस से एलिवेटेड नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध रूप से जुड़ा होगा, जिससे सुचारू मल्टीमॉडल एकीकरण सुनिश्चित होगा और शहर में भीड़भाड़ में कमी आएगी।

रेल पटरियों के ऊपर 15 एकड़ में फैला कॉनकोर्स प्लाज़ा और 7 एकड़ का मेजेनाइन प्लाज़ा बनाया जाएगा, जिसमें यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, शौचालय, फूड कोर्ट, खुदरा दुकानें आदि सुविधाएं होंगी। यह पुनर्विकसित स्टेशन एक ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित होगा, जो ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर केंद्रित रहेगा। स्टेशन में अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकें, स्वचालित पार्सल डिपो सिस्टम और दिव्यांगजन-अनुकूल संरचना (लिफ्ट एवं एस्केलेटर सहित) सुनिश्चित की गई हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास परियोजना न केवल आधुनिक अवसंरचना का प्रतीक बनेगी, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत को भी संजोए रखते हुए अहमदाबाद को एक प्रमुख वैश्विक महानगर के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी।

बिहार से कांग्रेस-राजद का होगा सफाया: अमित शाह ने शिवहर और सीतामढ़ी में गरजकर भरी हुंकार

(जीएनएस)। पटना/शिवहर। बिहार की सियासी फिज़ा सोमवार को तब गर्मा उठी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवहर और सीतामढ़ी जिलों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया और दावा किया कि इस बार बिहार की जनता कांग्रेस और राजद का सूपड़ा साफ कर देगी। शाह ने कहा कि बिहार की जनता राजग (NDA) को भारी बहुमत से सत्ता में लाने जा रही है और 14 नवंबर दोपहर एक बजे तक लालू-राहुल की राजनीति पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

अमित शाह ने कहा—"मैं आज ही बिहार चुनाव का परिणाम बता देता हूं। इस बार न लालू का लाल बचेगा, न सोनिया का लाल। बिहार में विकास की लहर है और यह लहर सीधी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के पक्ष में जा रही है।"

शाह के भाषण में आत्मविश्वास, हमला और विकास की बातों का मिला-जुला स्वर था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में विकास का चेहरा हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सेवा और सुशासन का प्रतीक हैं।

उन्होंने कहा, "लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री, लेकिन बिहार की जनता यह कभी नहीं होने देगी। बिहार ने अब तय कर लिया है कि वह परिवारवाद की राजनीति को सदा के लिए दफना देगा।"

अमित शाह ने कहा कि जब देश में मोदी और बिहार में नीतीश की जोड़ी है, तो जंगलराज लौटकर नहीं आएगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब अपराध कम हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, बिजली हर घर तक पहुंची है और केंद्र सरकार ने राज्य को अभूतपूर्व आर्थिक सहायता दी है।

उन्होंने आंकड़ों के साथ यह बताया कि यूपीए सरकार के दस वर्षों में बिहार को केवल 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये मिले थे, जबकि एनडीए सरकार ने पिछले दस वर्षों में 18 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया। शाह ने कहा—"यह है विकास की राजनीति। यह है सेवा की भावना। और यही फर्क है एनडीए और महागठबंधन के बीच।"

विपक्ष को बताया 'महाठगबंधन'

अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा—"यह कोई महागठबंधन नहीं, यह महाठगबंधन है। इनके पास न नेता है, न नीति। इन्हें खुद नहीं पता कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ रहा है। ये लोग केवल कुर्सी के लिए साथ आते हैं और चुनाव खत्म होते ही बिखर जाते हैं।"

उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसे बेमेल गठबंधनों को पहचान चुकी है, जिनका लक्ष्य जनता की सेवा नहीं बल्कि सत्ता की चाबी पाना होता है।

सीतामढ़ी से अयोध्या के बीच वंदे भारत ट्रेन की घोषणा

अमित शाह ने अपने संबोधन में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सीतामढ़ी में देवी सीता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन, सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अब सीतामढ़ी में माता सीता के जन्मस्थल के भी दर्शन कर सकेंगे। इससे बिहार के धार्मिक पर्यटन को बड़ा लाभ मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

राहुल गांधी पर निशाना

शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने छठी मैया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है। यह बिहार की आस्था पर चोट है। जब-जब राहुल गांधी ने मोदी जी का अपमान किया, जनता ने उन्हें हर बार हराकर जवाब दिया है। इस बार सीतामढ़ी की जनता छठी मैया का अपमान नहीं भूलेगी।"

किसानों को लेकर बड़ी घोषणा

सभा के दौरान अमित शाह ने किसानों के लिए एक बड़ा वादा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली वार्षिक राशि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और आने वाले वर्षों में इसका परिणाम साफ दिखाई देगा।

उन्होंने यह भी कहा कि दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर के हवाई अड्डों को जल्द ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा, जिससे बिहार का व्यापार, पर्यटन और निवेश तेजी से बढ़ेगा।

नीतीश-मोदी की जोड़ी को बताया विकास की गारंटी

शाह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की जोड़ी विकास और स्थिरता की गारंटी है। उन्होंने कहा—"बिहार ने जंगलराज से मुक्ति पाई है, और अब यह राज्य प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस विकास को रोकने की कोशिश जो भी करेगा, जनता उसे जवाब देगी।"

सभा के अंत में अमित शाह ने भीड़ से अपील की कि बिहार को फिर से पीछे नहीं जाने देना है। उन्होंने कहा—"यह चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं, बिहार की आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। विकास, सुशासन और स्थिरता के लिए बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए को ही चुनने जा रही है।"

सभा समाप्त होते-होते जय श्रीराम, भारत माता की जय और नीतीश-मोदी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। लोग अपने हाथों में भाजपा और जदयू के झंडे लहराते हुए विश्वास से भरे नजर आए—मानो बिहार की राजनीति में एक बार फिर सत्ता की लहर एनडीए के पक्ष में बह निकली हो।

पूर्वोत्तर को 635 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम से दी नई शुरुआत

(जीएनएस)। गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "विकसित पूर्वोत्तर" के विज़न को नई गति देते हुए केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को असम को 635 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। गुवाहाटी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने उत्तर पूर्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एनईएसटी) क्लस्टर का उद्घाटन किया और कई आधारभूत परियोजनाओं की नींव रखी।

कार्यक्रम में सिंधिया ने कहा कि "पूर्वोत्तर अब विकास का द्वार बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह क्षेत्र अब 'लैंड लॉक्ड' नहीं, बल्कि 'लैंड लिंक्ड' बन रहा है — यानी एशिया के बाजारों से सीधा जुड़ने वाला भविष्य का आर्थिक गलियारा।"

कुल 635 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में 65 नए माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण, चायगांव–उकिउम सड़क का उन्नयन, सिलोनिजन–धनसिरी पार घाट पर आरसीसी पुल का निर्माण, और कोकराझार व बक्सा जिलों में औद्योगिक परिसरों की स्थापना जैसी योजनाएँ शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "इन परियोजनाओं से न केवल शिक्षा और परिवहन में सुधार होगा, बल्कि

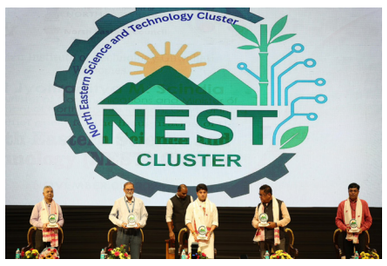

स्थानीय उद्योग और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।"

आईआईटी गुवाहाटी परिसर में लगभग 22.98 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित एनईएसटी क्लस्टर (North East Science and Technology Cluster) को पूर्वोत्तर भारत के नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास का नया केंद्र बताया जा रहा है। यह केंद्र स्थानीय नवाचार, सेमीकंडक्टर एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बांस आधारित तकनीक और जैव-प्लास्टिक निर्माण जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और उद्योग सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण महिलाओं की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि "पूर्वोत्तर की महिलाएँ केवल परिवारों की नहीं, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ हैं।" सिंधिया ने कार्यक्रम में भाग लेने वाली 30 ग्रामीण महिलाओं को सम्मानित किया, जिन्होंने जैव अपघटनीय खिलौनों के निर्माण में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार इन महिलाओं को सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।

एनईएसटी क्लस्टर के प्रतीक चिन्ह (लोगो) का अनावरण भी किया गया, जिसे इन्हीं ग्रामीण महिलाओं ने डिजाइन किया है — यह "स्थानीय से वैश्विक" (Local to Global) के सिद्धांत का प्रतीक माना जा रहा है। सिंधिया ने कहा कि पिछले दशक में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में अभूतपूर्व निवेश किया है। उन्होंने बोगीबील पुल, भूपेन हजारिका सेतु, सेला सुरंग और जोगीघोपा मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जैसी परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि "इन संरचनाओं ने न केवल संपर्क व्यवस्था बदली है, बल्कि असम और पूरे पूर्वोत्तर की आर्थिक गतिविधियों को नई उड़ान दी है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत का भविष्य पूर्वोत्तर की प्रगति से जुड़ा है — और आज का यह कदम उस उज्ज्वल, आत्मनिर्भर और प्रौद्योगिकी-प्रधान भारत की दिशा में एक ठोस शुरुआत है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सोमवार दोपहर बाद बेमौसम बरसात से प्रभावित गिर सोमनाथ और जूनागढ़ जिले के दौरे पर रवाना होंगे

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल हाल ही में हुई बेमौसम बरसात से प्रभावित गिर सोमनाथ और जूनागढ़ जिले की स्थिति के निरीक्षण के लिए आज यानी सोमवार दोपहर बाद इन जिलों के गांवों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री किसानों पर आई इस प्राकृतिक आपदा में उनके साथ खड़े रहने की संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ गिर सोमनाथ की कोडिनार तहसील के कड़वासण गांव और जूनागढ़ जिले की माळिया तहसील के पाणीद्रा गांवों के प्रभावित किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर जमीनी स्तर पर स्थिति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ गिर सोमनाथ जिले के कड़वासन गांव के दौरे में मंत्री सर्वश्री अर्जुनभाई मोढवाडिया और डॉ. प्रद्युमनभाई वाजा तथा जूनागढ़ जिले के पाणीद्रा गांव के दौरे में राज्य मंत्री श्री कौशिक वेकरिया भी मौजूद रहेंगे।

एलआईसी एजेंट से 1.35 करोड़ की ठगी, ऊंचे ब्याज का लालच देकर रकम हड़पी

(जीएनएस)। बरेली। निवेश के नाम पर ऊंचे ब्याज का लालच देकर एक एलआईसी एजेंट से करोड़ों रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपनी वर्षों की जमा-पूंजी और ग्राहकों की रकम एक फाइनेंस कंपनी में निवेश कर दी, लेकिन कुछ महीनों बाद कंपनी ने ब्याज देना बंद कर दिया और अब पूरा मूलधन भी डूबने की कगार पर है। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महावीर इंक्लेव फेस-2 निवासी मीरा गुप्ता, जो पेशे से एलआईसी एजेंट हैं, ने थाना बारादरी में दी गई तहरीर में बताया कि मॉडल टाउन निवासी कन्हैया गुलाटी, हरेंद्र पटेल और जगतपाल सिंह ने उन्हें ऊंचे ब्याज का लालच दिया था। उन्होंने बताया कि तीनों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी कंपनी में निवेश करने पर 5 प्रतिशत मासिक ब्याज मिलेगा, और पहले कुछ महीनों तक भुगतान भी किया गया। इससे भरोसा बढ़ा और उन्होंने अपनी ओर से तथा कुछ ग्राहकों की ओर से मिलाकर करीब 1.35 करोड़ रुपये कंपनी में लगा दिए।

शुरुआती कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य चला, लेकिन जल्द ही कंपनी ने ब्याज का भुगतान बंद कर दिया। जब मीरा गुप्ता ने रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने उन्हें पोस्ट डेटेड चेक दिए, जो अब तक कैश नहीं हुए। इस दौरान बार-बार संपर्क करने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे संगठित आर्थिक ठगी का शिकार हो चुकी हैं।

पीड़िता ने बताया कि उन्होंने अधिक ब्याज और बेहतर रिटर्न के लालच में अपना घर गिरवी रखकर 39 लाख रुपये का लोन लिया था, और वह राशि भी पूरी की पूरी फाइनेंस कंपनी में निवेश कर दी थी। अब न तो ब्याज मिल रहा है, न मूलधन लौटाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों ने निवेशकों को विश्वास में लेकर नकली एग्रीमेंट और झूठे दस्तावेजों के सहारे करोड़ों रुपये हड़प लिए हैं।

थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि आरोपियों कन्हैया गुलाटी, हरेंद्र पटेल और जगतपाल सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि यही कंपनी शहर के अन्य इलाकों में भी लोगों को ऊंचे ब्याज का झांसा देकर निवेश करा चुकी है और अब कई निवेशकों के लाखों रुपये फंसे हुए हैं।

शहर में चर्चा और निवेशकों में दहशत

घटना के बाद बरेली में बीमा एजेंटों और निवेशकों में भारी चिंता का माहौल है। कई लोगों ने बताया कि आरोपी लंबे समय से स्थानीय निवेशकों के बीच भरोसा कायम करने में जुटे थे और छोटे-बड़े कई एजेंटों को अपनी कंपनी से जोड़ लिया था। पुलिस अब कंपनी के बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच कर रही है।

जयेश लॉजिस्टिक्स ने शेयर बाजार में दी कमजोर शुरुआत, निवेशकों को पहले दिन ही नुकसान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की लॉजिस्टिक सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जयेश लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के शेयरों की शुक्रवार को एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हुई, लेकिन उम्मीदों के विपरीत यह शुरुआत कमजोर रही। कंपनी का शेयर 122 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 120 रुपये प्रति शेयर पर खुला, यानी करीब 1.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ। कारोबार के पहले ही घंटे में भारी बिकवाली देखने को मिली और शेयर 114 रुपये के लोअर सर्किट तक जा पहुंचा।

हालांकि, दोपहर के बाद बाजार में कुछ लिवाली लौटी, जिससे शेयर में हल्की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन कारोबार के अंत में यह 117.80 रुपये पर बंद हुआ। इस तरह पहले ही दिन निवेशकों को 3.44 प्रतिशत यानी 4.20 रुपये प्रति शेयर का घाटा हुआ।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह नतीजा अल्पकालिक मुनाफावसूली और छोटे निवेशकों की त्वरित बिकवाली प्रवृत्ति का परिणाम है।

जयेश लॉजिस्टिक्स का 28.63 करोड़ रुपये का आईपीओ 27 से 29 अक्टूबर के बीच खुला था और इसे निवेशकों का शानदार प्रतिसाद मिला था। यह इश्यू कुल 65.59 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें खुदरा निवेशकों और एनआईआई (Non Institutional Investors) दोनों की भागीदारी जबरदस्त रही। इसके बावजूद लिस्टिंग के दिन शेयर बाजार का भरोसा कमजोर रहा।

कंपनी ने अपने आईपीओ से जुटाई गई पूंजी का उपयोग साइड वॉल ट्रेलर्स की खरीद, वर्किंग कैपिटल जरूरतों और कॉरपोरेट कार्यों के लिए करने की घोषणा की थी। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, मजबूत सब्सक्रिप्शन के बावजूद कमजोर लिस्टिंग यह दर्शाती है कि निवेशकों को कंपनी के शॉर्ट टर्म ग्रोथ आउटलुक को लेकर अभी भी संदेह है।

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो पिछले तीन वर्षों में राजस्व और मुनाफे दोनों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। सेबी के पास दाखिल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के मुताबिक,

वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी ने 1.09 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था, जो 2023-24 में बढ़कर 3.16 करोड़ रुपये और 2024-25 में 7.20 करोड़ रुपये हो गया।

इसी अवधि में कंपनी का राजस्व 60.37 करोड़ रुपये से बढ़कर 112.03 करोड़ रुपये तक पहुंचा।

हालांकि, इस तेज विस्तार के साथ कर्ज का बोझ भी बढ़ा है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में कंपनी पर कुल देनदारियां 29.65 करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं। यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि बढ़ते कर्ज के बीच लाभप्रदता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है।

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि जयेश लॉजिस्टिक्स को अब लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान देना होगा। कंपनी का व्यवसाय मॉडल मजबूत है, लेकिन निवेशकों का भरोसा तभी लौटेगा जब यह लगातार सतत मुनाफा और कैश फ्लो दिखा पाएगी।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती कमजोरी के बावजूद यह स्टॉक मध्यम अवधि में स्थिरता हासिल कर सकता है, यदि कंपनी अपनी परिचालन दक्षता और डिलीवरी नेटवर्क को विस्तार देती है।

फिलहाल, निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय कंपनी के आगामी वित्तीय नतीजों और संचालन प्रदर्शन पर नजर रखें, क्योंकि लॉजिस्टिक्स सेक्टर आने वाले समय में भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर और ई-कॉमर्स ग्रोथ से सीधा लाभ उठाने की स्थिति में है।

महाराष्ट्र में फसल बीमा घोटाले पर केंद्र सख्त, शिवराज सिंह चौहान ने दिए जांच के आदेश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों को केवल 1 से 21 रुपये तक के बीमा क्लेम मिलने के मामलों ने केंद्र सरकार को सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। किसानों के साथ इस तरह के मजाक पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को तत्काल जांच के आदेश देते हुए कहा कि इस योजना की आड़ में किसी भी प्रकार की लापरवाही या धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

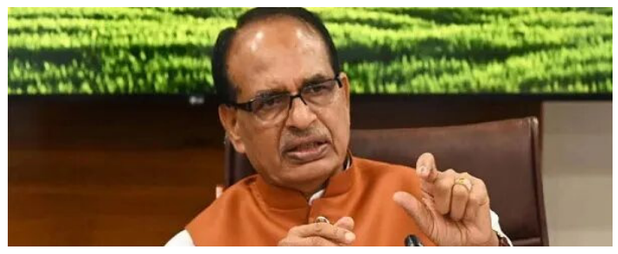

दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मंत्री ने इस मुद्दे पर गहरी नाराजगी जताई। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों और महाराष्ट्र के कुछ किसानों को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा गया, जहां किसानों ने अपने अनुभव सीधे मंत्री को बताए। किसानों की शिकायतें सुनने के बाद चौहान ने सख्त लहजे में कहा, "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का सुरक्षा कवच है, इसे मज़ाक का विषय नहीं बनने दिया जाएगा। किसी किसान को 1 रुपये या 21 रुपये का क्लेम देना शर्मनाक है। जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी।"

शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फील्ड स्तर पर तुरंत जांच शुरू करें और यह पता लगाएं कि आखिर किस स्तर पर गड़बड़ी हुई। उन्होंने कहा कि किसानों को सही मूल्यांकन के आधार पर उनका हक मिलना चाहिए, न कि कागज़ी आंकड़ों पर। मंत्री ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सरकार फसल नुकसान आकलन प्रणाली में व्यापक सुधार करेगी और योजना के प्रावधानों में संशोधन भी किया जाएगा।

बैठक में यह भी खुलासा हुआ कि कई राज्य सरकारें फसल बीमा योजना में अपने हिस्से की सब्सिडी समय पर जमा नहीं कर रही हैं, जिससे किसानों को क्लेम मिलने में देरी हो रही है। इस पर चौहान ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि "अब राज्य सरकारें यदि अपनी हिस्सेदारी समय पर नहीं जमा करेंगी तो उनसे 12 प्रतिशत ब्याज वसूला जाएगा।" उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्यों की लापरवाही का बोझ किसानों पर नहीं डाला जाएगा और केंद्र सरकार हर हाल में किसानों के साथ खड़ी है।

शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र में किसानों से मिली शिकायतों और महाराष्ट्र के ताज़ा मामलों का हवाला देते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना किसानों के लिए वरदान है। कुछ अफसरों और बीमा कंपनियों की लापरवाही से इस योजना की साख पर दाग नहीं लगने दिया जाएगा।"

बैठक के अंत में उन्होंने यह भी घोषणा की कि फसल बीमा योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय शीघ्र ही व्यापक सुधार लागू करेगा।

आयुष मंत्रालय ने 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान से न सिर्फ स्वच्छता बढ़ाई, बल्कि कमाए 7.35 लाख रुपये

(जीएनएस)। नई दिल्ली। 'स्वच्छ भारत' के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आयुष मंत्रालय ने 'विशेष अभियान 5.0' के तहत देशभर में व्यापक सफाई और प्रशासनिक सुधार का एक बड़ा कार्यक्रम चलाया। इस दौरान मंत्रालय ने कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी से कुल 7 लाख 35 हजार रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता और संसाधनों के पुनः उपयोग का एक सफल उदाहरण बन गया है।

अभियान के दौरान मंत्रालय ने 1365 वर्ग फुट कार्यालय क्षेत्र को खाली कराया, जिससे कार्यस्थलों में स्वच्छता, व्यवस्था और उपयोगी जगह का विस्तार हुआ। इसके साथ ही मंत्रालय ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में भी कई ठोस कदम उठाए — कुल 658 जन शिकायतों और 59 अपीलों का निस्तारण किया गया। पुराने दस्तावेजों के प्रबंधन को सुधारने के लिए 101 अप्रासंगिक फाइलों को नष्ट किया गया ताकि रिकॉर्ड प्रणाली अधिक पारदर्शी और कुशल बन सके।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक पूरे देश में आयुष मंत्रालय से जुड़े कार्यालयों में एक साथ चलाया गया। इसका उद्देश्य केवल सफाई तक सीमित नहीं था, बल्कि सरकारी कार्यशैली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दक्षता लाने पर भी जोर दिया गया। इस विशेष अभियान के तहत पूरे देश में आयुष से संबद्ध संस्थानों में 68 सफाई अभियान आयोजित किए गए, जिनमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं आयुष भवन सहित अन्य प्रमुख कार्यालयों में झाड़ू उठाकर सफाई की, जिससे कर्मचारियों में नई प्रेरणा का संचार हुआ।

अभियान के अंत में मंत्रालय ने कहा कि "स्वच्छता केवल एक दिवस या सप्ताह की पहल नहीं, बल्कि यह हमारी कार्यसंस्कृति का स्थायी हिस्सा बननी चाहिए।" इस प्रयास के माध्यम से आयुष मंत्रालय ने यह संदेश दिया कि स्वच्छता और प्रशासनिक सुधार एक साथ चल सकते हैं, और सही दृष्टिकोण अपनाने पर इससे न केवल कार्यस्थल सुंदर बनते हैं बल्कि आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है।

केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब परियोजनाओं की प्रगति का ब्योरा हासिल करने के लिए गांधीनगर में की बैठक

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर विशेष फोकस के साथ एक अभियान शुरू किया गया है : आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया की उपस्थिति

श्री अश्विनी वैष्णव :-

- धोलेरा आगामी समय में हाईटेक उत्पादन का बड़ा केंद्र बनेगा
- देश और गुजरात के सेमीकंडक्टर सेक्टर पर दुनिया के लगभग सभी देशों की नजर है, और सेमीकॉन इंडस्ट्री के संदर्भ में धोलेरा का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सेमीकॉन क्षेत्र में लीडर बनेगा
- सेमीकंडक्टर सेक्टर के विकास पर फोकस करने के लिए टाइम बाउंड प्लानिंग और नियमित फॉलो-अप तथा सटीकता के साथ कार्य पूर्ण करने के दिशानिर्देश

(जीएनएस)। गांधीनगर : सूचना एवं प्रसारण, रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर विशेष फोकस के साथ एक अभियान शुरू किया गया है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर उत्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ये क्षेत्र बहुत तेजी से और अच्छी प्रगति कर रहे हैं।

मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब की परियोजनाओं की प्रगति का ब्योरा हासिल करने के लिए सोमवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप

मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की।

उन्होंने इस बैठक में विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से धोलेरा और साणंद में निर्माणाधीन टाटा, माइक्रोन और सीजी सेमीकॉन जैसे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा रेल, रोड एवं एयर कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन जानकारी हासिल की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बैठक में कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पहले भी अनेक प्रयास किए गए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शासन दायित्व संभालने के बाद ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं भारत में कार्यरत होने जा रही हैं। लोगों को विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सेमीकॉन क्षेत्र में लीडर बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सेमीकॉन हब के रूप में गुजरात की अगुवाई का जो वातावरण तैयार हुआ है, उसे बनाए रखते हुए सेमीकंडक्टर सेक्टर के विकास पर फोकस करने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर टाइम बाउंड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने नियमित फॉलो-अप बैठक आयोजित करने और सारे कार्यों को समय पर तथा सटीकता के साथ पूरा करने के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास व्यक्त किया कि धोलेरा आगामी समय में हाईटेक उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि देश और गुजरात के सेमीकंडक्टर सेक्टर पर दुनिया के लगभग सभी देशों की नजर है और सेमीकॉन इंडस्ट्री के संदर्भ में धोलेरा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है।

ऐसी स्थिति में भारत में पहली सेमीकंडक्टर चिप को पूरी तरह से कार्यात्मक करने के लिए निर्धारित किए गए समय के दौरान ही वह तैयार हो, इसकी बड़ी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार को निभानी है।

मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस बैठक में लगभग 10 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स का ब्योरा हासिल किया और निर्देश दिए कि इससे जुड़े मामलों के लिए नियमित रूप से फॉलो-अप बैठकें आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभाग सेमीकंडक्टर उद्योगों को आवश्यक मदद के लिए 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों के वरिष्ठ सचिव तथा टाटा, सीजी सेमीकॉन और माइक्रोन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।